पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं. HP/DMA/113

Changing Ways
बदलती राहें
(साप्ताहिक)

❑ वर्ष 01 ❑ अंक 14 ❑ पृष्ठ : 04 ❑ मूल्य : 4 रुपये धर्मशाला, 13 जून 2016 हर सोमवार को प्रकाशित

छोटे राज्य में बड़ी घोषणाएं अच्छे दिनों का संकेत

धर्मशाला। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के अच्छे दिन आते दिख रहे हैं।

यह पहली बार है जब भारत के इस छोटे से विकासशील पहाड़ी राज्य पर किसी केंद्र सरकार ने खास तवज्जो दी है। बड़े-बड़े राज्यों के किसी एक शहर के बराबर आबादी वाले इस राज्य पर हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं का ऐलान किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार ने इस राज्य का स्पेशल स्टेटस बहाल करके पहले ही इसकी तरक्की को पंख देने की अपनी मंशा जाहिर कर दी थी, मगर हाल ही के कुछ महीनों में जो घटित हुआ है उस पर किसी भी हिमाचली को यकीन करना मुश्किल हो रहा है। सिर्फ सड़कों के विकास पर ही एक साथ 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने की मजूरी देना कोई छोटी बात नहीं है। प्रदेश में एक नहीं एक साथ 45 राष्ट्रीय राजमार्गों की ताबड़तोड़ घोषणा कर दी गई है। पहाड़ी राज्य की जीवन रेखा कही जाने वाली लगभग सभी महत्वपूर्ण सड़कों को केंद्र सरकार के भूतल एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा गोद लिया जाना इस प्रदेश की विकास गाथा का नया अध्याय कहा जा सकता है। इस अकल्पनीय गाथा की पटकथा पिछले छह मई को केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के धर्मशाला दौरे से हुई थी। हालांकि तब वे परिवार सहित यहां छुट्टियां मनाने पहुंचे थे, मगर प्रदेश सरकार की मेजबानी से खुश होकर उन्होंने होटल धौलाधार में पत्रकारवार्ता के दौरान ही एक साथ 17 राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करके प्रदेश के लिए खास ऐलान का संकेत दे दिया था।

■ शेष पृष्ठ 2 पर

यह है गडकरी का हिमाचल विज़न

हमीरपुर। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं पोत मंत्री नितिन गडकरी ने हमीरपुर में आयोजित जनसभा में हिमाचल को लेकर अपना विजन स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश में सुंदर पहाड़ियां हैं। ऐसे दृश्य आम तौर पर देखने को नहीं मिलते है। पर्यटक यहां आना चाहते हैं, लेकिन वे आ नहीं सकते। वजह यह है कि यहां आने के लिए उचित मार्ग एवं अन्य साधन नहीं है। यदि पर्यटक यहां नहीं आएगा तो आय नहीं होगी।

पर्यटन से ही करीब 45 प्रतिशत प्रदेश की आय होगी, इसके लिए जरूरी है कि मार्गों का विकास किया जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका धनवान इसीलिए है कि वहां मार्गों का विकास सही तरीके से किया गया है। उन्होंने कहा कि देश का विकास करवाना है तो देश में विकास की राजनीति की भी जरूरत है। रास्ते अच्छे बनेंगे तो हिमाचल देश का सबसे धनवान प्रदेश बनकर उभरेगा।

शिमला से धर्मशाला तक महामार्ग

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने घोषणा की है कि शिमला-धर्मशाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग को अब राष्ट्रीय महामार्ग बनाया जाएगा। इसके लिए पांच हजार करोड़ से ज्यादा खर्च आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अगले छह माह के अंदर इसकी डीपीआर बनाकर कार्य शुरू करवाया जाएगा। ज्ञात रहे क इस मार्ग पर प्रदेश की आधे से ज्यादा आबादी सफर करती है। इस हाईवे के बनने से प्रदेश की एक-तिहाई से भी ज्यादा आबादी सहित राज्य में आने वाले पर्यटकों को कम समय में राजधानी शिमला से लेकर बाकी पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। वहीं सड़क हादसों में भी कमी आएगी।

रेलवे क्रासिंग पर बनेंगे पांच ओवर ब्रिज

जिला कांगड़ा में रेलवे क्रासिंग से होने वाली परेशानी को समाप्त करने के लिए पांच ओवर ब्रिज बनाने को मंजूरी दी गई है। पांच सौ करोड़ रुपये खर्च करके मलां, भड्डू, अरला, बैजनाथ और एहजु में ओवर ब्रिज बनेंगे। उन्होंने दिसंबर माह से पूर्व इन पुलों पर काम शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने परिवहन मंत्री जीएस बाली की नगरोटा बगवां में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर हेड ब्रिज बनाने की मांग को भी स्वीकृत कर लिया है।

दुर्घटनाएं घटाने को 11 हजार करोड़

नितिन गडकरी ने बताया कि देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ब्लैक स्पॉट की पहचान करके इन्हें दुरुस्त करने की योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके बाद ऐसे ७२६ मामले आए हैं, उन पर ११ हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने हिमाचल सरकार से कहा है कि प्रदेश सरकार ऐसे ब्लैक स्पाट चिन्हित करके उनके मंत्रालय को भेजे तो उचित बजट मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश में हर रोज पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें तीन लाख लोग मारे जाते हैं और डेढ़ लाख के करीब घायल होते हैं।

शिमला बाईपास के लिए 16 सौ करोड़

कैथलीघाट से शिमला तक बनने वाले इस बाईपास पर 1600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 14 मई तक इसके फाइनल टेंडर भी जारी कर दिए जाएंगे और जून माह तक इसका कार्य भी शुरू करवा दिया जाएगा।

ट्रांस्पोर्ट के विकल्पों पर विचार करे सरकार

नितिन गडकरी ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार प्रदूषण रहित परिवहन की व्यवस्था करने का खाका तैयार करके उन्हें सौंपती है तो परिवहन के वैकल्पिक व पर्यावरण फ्रेंडली साधनों की व्यवस्था करने में पूरी मदद की जाएगी। इनमें रोप-वे अच्छा साधन हो सकता है।

उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर व अरुणाचल में इलैक्ट्रोनिक ट्रांस्पोर्ट लाने की योजना है। इसके तहत उनके मंत्रालय ने जर्मनी, नर्वे, आस्ट्रेलिया व स्वीडजरलैंड की तकनीक की जानकारी प्राप्त की है। इसके तहत पब्लिक-प्राईवेट निवेश के जरिये बिजली और इससे चलने वाले यातायात के साधनों की व्यवस्था की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क मार्ग बनाना बड़ा मुश्किल होता है। यहां सुरंगें बनाने पर ही काफी बजट खर्च हो जाता है। यहां वैनेकुलर रेलवे एक बढ़िया विकल्प हो सकता है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली भी काफी सस्ती है। इस लिहाज से एक यूनिट बिजली से एक लीटर पेट्रोल या डीजल के बराबर दूरी तय की जा सकती है। इससे जहां प्रदूषण कम होगा, वहीं यातायात का सस्ता साधन भी उपलब्ध होगा और पैट्रोल/डीजल के आयात पर होने वाला खर्च भी बचेगा।

ये हैं हाल ही में घोषित नए एनएच

1. धनेटा-बड़सर-शाहतलाई-बरठीं-भगेड़
2. हलिपारा-डाडासिबा-संसारपुर टैरेस
3. भरवाईं-चिंतपूर्णी-जोड़बड़-पक्का टियाला-संसारपुर टैरेस
4. रानीताल-लंज-मसरूर
5. सुनहेत-बधु-मचकुंड महादेव-डाडासिबा-पुलवाड़ा
6. जलाड़ी-कांगू-गलोड़-सलौणी-बिझड़ी-बरठी-घुमारवीं
7. जिहण-रंगस-धनेटा-बंगाणा
8. संतोषगढ़-टाहलीवाल-हरोली-सलोह-गगरेट-तलवाड़ा-मरवाड़ी
9. हमीरपुर-दोसड़का-तरक्वाड़ी-भोरंज-जाहू
10. ज्वालामुखी-देहरा-ज्वाली-राजा का तालाब
11. अजोली-संतोषगढ़-ऊना-लोअर लालसिंगी-स्वांपुल
12. कैंची मोड़-भाखड़ा वाया श्री नैनादेवी
13. मसरूर-धंगड़-गुलेर-नंदपुर-नगरोटा सूरियां-पुलनंद नाला
14. नगाओ-बैरी-दाड़ला मोड़

■ शेष पृष्ठ 2 पर

पठानकोट-जोगिंद्रनगर रेल ब्राडगेज करने का सर्वे शुरू

पहाड़ पर बड़ी रेलगाड़ी के सपने को भी लगे पंख

मंडी। मोदी सरकार ने देवभूमि की सड़कों ही नहीं बल्कि रेल मार्ग के विस्तार के सपने को भी पंख देना शुरू कर दिए हैं। अंग्रेजों के शासनकाल के बाद से जिस राज्य में रेल विस्तार के नाम पर महज मैदानी क्षेत्र की चंद किमी. रेललाइन ही आगे बढ़ पाई हो, वहां एक छोर से दूसरे छोर तक बड़ी रेलवे लाइन बिछाने के प्रयास किसी स्वप्न के सच होने के समान हैं। शायद ही कोई हिमाचली हो, जो आजादी के बाद से पेश किए जाने वाले रेलवे बजट को देखकर आह न भरता रहा हो। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल की रेलवे को विस्तार देने का मामला जोर पकड़ता आ रहा है, मगर यह पहली बार है कि किसी केंद्र सरकार ने हिमाचल में सड़क के अलावा रेलवे विस्तार की बात भी सोची है। आजादी से पूर्व 1928 अंग्रेज अधिकारी मेंकर्नल बैटी द्वारा शानन परियोजना के लिए बिछाई गई पठानकोट-जोगिंद्रनगर रेलवे लाईन पर अब टॉय ट्रेन की जगह बड़ी रेल गाड़ी दौड़ेगी और वो भी मंडी होती हुई लेह तक जाएगी। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 660 किलोमीटर लंबे इस रेलवे ट्रैक का सर्वे भारतीय रेलवे की ओर से शुरू हो गया है। भारतीय रेल के वरिष्ठ ट्रैफिक अधिकारी रणवीर सिंह की अगुवाई में सर्वे टीम मंडी पहुंची है। कुल्लू-मनाली, रोहतांग होते हुए लेह तक के इस पूरे ट्रैक का सर्वे करके यह टीम भारतीय रेलवे को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

◆ रेलमार्ग को पहले चरण में मंडी तक ले जाया जाएगा
◆ फिर मनाली व रोहतांग होते हुए लेह तक जाएगा रेलमार्ग

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी रणवीर सिंह के अनुसार पठानकोट-जोगिंद्रनगर नेरोगेज को ब्राडगेज किया जाना है। इसे मंडी तक बढ़ाया जाएगा। जोगिंदनगर से मंडी तक चार रेलवे क्रासिंग बनेंगे। इनमें चलोंटी, सुराहन, टांडू और मंडी शामिल हैं। जबकि मंडी में रेलवे टर्मिनल बनाया जाना प्रस्तावित है। इस ट्रैक पर कुछ सुरंगें भी प्रस्तावित हैं। इससे एक तो रेलवे ट्रैक की दूरी कम कम हो जाएगी।

■ शेष पृष्ठ 2 पर

लोकतंत्र के स्तंभ हदों में रहें तो ही बेहतर

भारत में जो हो रहा है, वह विधायिका का पतन और न्यायपालिका में आई विकृति ही है। न्यायाधीशों ने खुद अपने को नियुक्त, अनुशंसित और तो और रिटायरमेंट के बाद फिर तरह-तरह के आयोगों, अधिकरणों में पुनर्नियुक्त होने-करने की ताकत झटक ली है। इसका भारत के संविधान या सामान्य न्याय-विवेक से कोई लेना-देना नहीं है। यह एक तरह से खालिस मनमानी ही है।

- शंकर शरण

न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद की खबरें लगातार आ रही हैं। वित्त मंत्री ने संसद में कहा न्यायपालिका इतना हस्तक्षेप कर रही है कि लगता है कार्यपालिका के पास बजट पास करने के सिवाय कोई काम नहीं बचेगा। न्यायपालिका हर बात में घुसपैठ करती रहती है। इसके बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि न्यायाधीशों की कई टिप्पणियां बेमतलब होती हैं। इसके बाद एक और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर के उस बयान का प्रतिकार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जब सरकार फेल हो जाती है, तभी न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है।

लगता है कि सरकार के दो अंगों के बीच तकरार बढ़ रही है। कोई पक्ष यह नहीं कह सकता कि वही ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायपाल कुछ यही मुद्रा दिखा रहा है। वह मानने को तैयार नहीं कि विधायिका एवं कार्यपालिका के कामों में दखलंदाजी, हल्की टिप्पणियां करने और खुद अपनी नियुक्ति करने जैसे अधिकार ले लेने में कुछ गलत है। अभी-अभी सहारा प्रमुख सुब्रत राय को पैरोल पर छोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने कहा, यह होता है मां का प्यार कि वह सरकार भी मदद कर जाती है। यह फिल्मी किस्म की टिप्पणी क्या दर्शाती है? यही कि न्यायाधीश कानूनी प्रावधानों के बदले भावनाओं और आवेगों को महत्व देते हैं? उन्हें यह एहसास भी नहीं कि न्यायिक फैसले देते हुए ऐसी बातें कहना सही संदेश नहीं देता।

दरअसल औसत नेताओं के अज्ञान और राजनीतिक दलों की आपसी खींचतान से विधायिका की स्थिति कमजोर हुई है। इसका लाभ अफसरशाही और न्यायपालिका उठा रही है। इसी क्रम में सर्वोच्च न्यायाधीशों ने खुद को नियुक्त और पुनर्नियुक्त करने की ताकत भी हथिया ली, जबकि सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम व्यवस्था यानी उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीश खुद तय करने की व्यवस्था न तो संविधानसम्मत है और न ही सामान्य विवेक से ठीक है। इसे संसद ने नहीं, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से शुरू किया। यदि इसे न्यायिक स्वतंत्रता के नाम पर सही मानें तब इसी तर्क से विधानसभाओं की कार्रवाइयों में हस्तक्षेप का अधिकार न्यायालयों को कैसे है? यह तो विधायिका की स्वतंत्रता में अनुचित हस्तक्षेप हुआ। नेताओं ने अपनी गैरजिम्मेदारी और दलीय-द्वेष से न्यायपालिका को वह अधिकार लेने दिया है, जो उसे संविधान ने नहीं दिया था। यदि उच्चतर न्यायपालिका अपने उत्तराधिकारी खुद तय कर रही है तो उच्चतर विधायिका और कार्यपालिका भी अपने उत्तराधिकारी वैसे ही क्यों न तय करे? यानी वरिष्ठ सांसदों की समिति निर्णय ले कि अगले सांसद कौन-कौन होंगे। आखिर जो जरूरत न्यायिक स्वतंत्रता के लिए है, वही विधायिका और कार्यपालिका की स्वतंत्रता के लिए भी है। सभी जगह मनुष्य ही काम करते हैं। मनुष्य वाली खूबियां-खामियां सबमें होंगी। हमारे न्यायपाल उससे मुक्त नहीं हैं। वे कितने ही स्वामी और बालाकृष्णन दिखा भी चुके हैं। सवाल यह भी है कि क्या कानूनी विवादों का फैसला करना देश की सीमाओं, जन-गण की रक्षा करने या संपूर्ण प्रशासन

चलाने से ज्यादा कठिन है? जब हम पता करें कि दुनिया के किस देश में न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी खुद नियुक्त करते हैं, तब पाएंगे कि भारत में विगत दो दशक से चल रही कोलेजियम व्यवस्था कितनी अनुचित है। व्यवहार में भी उसके परिणाम आदर्श नहीं कहे जा सकते। 23 वर्षों से चल रही इस स्वनियुक्ति प्रक्रिया से यदि उत्तमोत्तम न्यायाधीश आए होते तब भी एक बात थी, लेकिन देखा गया है कि ऐसे-ऐसे जजों को सुप्रीम कोर्ट लाया गया, जो हाई कोर्ट में ही तीन घंटे लेट आते थे। सुप्रीम कोर्ट आकर भी उनका यही रवैया रहा। इसी तरह ऐसे न्यायाधीश भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जो समय काटकर चले गए। एक न्यायाधीश ने निर्णय लिखने में महीनों देरी होने पर पूछने पर कहा था कि उन्हें निर्णय लिखने की तनख्वाह नहीं मिलती।

संघीय लोकतंत्र में किसी अंग की शक्तियों की वरिष्ठता नहीं, सभी अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण (सेपेरेशन ऑफ पावर) होता है। यही अमेरिका में भी है। वहां सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति यानी प्रमुख कार्यपाल अपने अधिकार से करता है। उसकी पुष्टि विधायिका करती है। न्यायाधीश खुद अपने को नियुक्त नहीं करते। वहां तो सरकार का कोई अंग अपने को नियुक्त नहीं करता। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, तीनों की नियुक्तियां दूसरे करते हैं, लेकिन नियुक्त हो जाने के बाद उसके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह सरकार के तीनों अंगों की स्वतंत्रता के साथ-साथ निगरानी और संतुलन यानी चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है, जो शक्तियों के पृथक्करण का सहयोगी सिद्धांत है।

भारत में जो हो रहा है, वह विधायिका का पतन और न्यायपालिका में आई विकृति ही है। न्यायाधीशों ने खुद अपने को नियुक्त, अनुशंसित और तो और रिटायरमेंट के बाद फिर तरह-तरह के आयोगों, अधिकरणों में पुनर्नियुक्त होने-करने की ताकत झटक ली है। इसका भारत के संविधान या सामान्य न्याय-विवेक से कोई लेना-देना नहीं है। यह एक तरह से खालिस मनमानी ही है। हैरत यह है कि इतनी ताकत जुटा लेने के बावजूद न्यायपालिका ने अपने में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, विलंब, सुनवाई मामलों के चयन में पक्षपात आदि दूर करने का कोई उपाय नहीं किया। 1989 में ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश सब्यसाची मुखर्जी ने न्यायपालिका में भारी भ्रष्टाचार को चिंताजनक बताया था। मामलों की प्राथमिकता तय करने के पैमाने भी समझ में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट में किसी केस को आठ-आठ साल तक छुआ नहीं जाता, जबकि किसी आतंकी पर बार-बार पुनर्विचार, किसी बड़ी कंपनी, नेता या राजनीतिक विवाद पर त्वरित सुनवाई अथवा क्रिकेट, मोटर-प्रदूषण, परीक्षा, सड़क सफाई आदि पता नहीं कितने तरह के रोजमर्रा के विषयों में नगरपालिका अधिकारी जैसे काम करते देखा गया है। इससे संविधान व कानून की देखरेख का मुख्य काम और नैतिक मानदंड तक उपेक्षित हुए। तीस्ता सीतलवाड़ की गुजरात संबंधी शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा उत्साह दिखाया कि दस्तावेजों की प्रामाणिकता संबंधी नियम तक की अनदेखी हो गई।

वस्तुतः शासन के तीनों अंगों की स्वतंत्रता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सबको अपने कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना और केवल दूसरों के दोष दिखाना अच्छा संदेश नहीं देता। न्यायपालिका को चुस्त, निष्पक्ष रखने के लिए न्यायिक शिक्षा से लेकर नियुक्ति तक, सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद शक्ति एवं सुविधा वाले पदों पर न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति का चलन भी खत्म करना जरूरी है। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की उक्ति साकार करने के लिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका, दोनों का सहयोग जरूरी है।

सौजन्य: नई दुनिया

पृष्ठ 1 के शेष

छोटे से राज्य...

तब उन्होंने प्रदेश की 1500 किमी. सड़कों को नेशनल हाईवे के तहत लाने की घोषणा की और प्रदेश सरकार को विकास के लिए राजनीति से ऊपर उठकर अपना हाथ फैलाने का निमंत्रण दे दिया था। इस दौरान उन्होंने जून माह में प्रदेश के औपचारिक दौरे का जिक्र करते हुए बड़ी घोषणाओं की बात कही थी। इसका नतीजा यह निकला कि पांच जून को जब वे हिमाचल दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने ऐसे तोहफे देने का ऐलान किया कि हर कोई भौंचक्का था। कोई इसे आने वाले चुनावों की तैयारी से जोड़कर देखने लगा तो कुछ लोग इससे अलग कयास लगाने लगे। हालांकि तरह-तरह के कयासों के बीच सभी ने गडकरी की उस बात को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे जब तक पद पर हैं अपना टारगेट पूरा करने को लालायित हैं। उनका टारगेट हर दिन 30 किमी. सड़कों का निर्माण करना है। ऐसे में हिमाचल जैसे शांत व कम भ्रष्टाचार वाले राज्य में उनको अपना टारगेट आसानी से पूरा होता दिख रहा था। ऐसे में उन्होंने भ्रष्ट व तरक्की पर कम ध्यान देने वाले राज्यों की तुलना में हिमाचल जैसे तरक्की पसंद पहाड़ी राज्य को अपने टारगेट का हिस्सा बनाने में जरा भी संकोच नहीं किया। वैसे भी कहा जाता है कि भाजपा ने हमेशा पहाड़ी राज्यों के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया है। फिलहाल अब पासा प्रदेश की वीरभद्र सिंह सरकार के पाले में है। केंद्र की घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने की सर्वाधिक जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की ही होती है। एनएच का निर्माण कोई आसान काम नहीं। इनकी डिपीआर बनाने और भूमि अधिग्रहण में ही सालों लग जाते हैं। ऐसे में इन 50 हजार करोड़ की योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल में लाना है तो प्रदेश सरकार व यहां की मशीनरी को उतनी ही तेजी से हरकत में लाना होगा, जितने तेजी से इन घोषणा हुई है।

पहाड़ पर बड़ी...

वहीं पर चढ़ाई और मोड़ आदि भी कम होंगे। रणबीर सिंह ने बताया कि नेरोगेज में जहां एक डिब्बे में मात्र 50 लोगों के बैठने की क्षमता होती है। वहीं पर ब्राडगेज में इसकी क्षमता बढ़कर 120 हो जाती है। जबकि नेरोगेज में पांच-छह डिब्बे जुड़ते हैं तो ब्रॉडगेज में इनकी संख्या बढ़कर पच्चीस हो जाएगी। इसके अलावा इसमें सामान ले जाने के लिए वीपीओ की सुविधा भी रहेगी। इसमें बागवानों और किसानों को अपने उत्पाद बाहर ले जाने में आसानी रहेगी। इसके अलावा ढ़ंग नमक कारखाने के उत्पाद और प्रस्तावित सीमेंट कारखानों से सीमेंट की ढुलाई भी रेलवे के माध्यम से होगी।

पाठकों के लिए

विभिन्न सामाजिक, साहित्यिक एवं धार्मिक विषयों पर सभी प्रबुद्ध पाठकों के लेख, लघु कथाएं तथा कविताएं आमंत्रित हैं।

हमारा पता

संपादक,
बदलती राहें, गुंजन भवन, तपोवन रोड वीपीओ सिद्धबाड़ी, धर्मशाला जिला कांगड़ा (हि.प्र.)-176057

Mail : badaltirahain@gmail.com

ये हैं हाल ही...

15. द्रमण-सिहुंता-चुवाड़ी-जोत-चंबा-तीसा-किलाड़
16. भरोड़-बरठीं-तलाई-बड़सर
17. भोटा-कलखल-नेरचौक-जाहू
18. रानीताल-कोटला
19. रोहड़ू-टिक्कर-नेहराघाटी-पनोग-दियोड़ी-कोटखाई
20. छैला-ओच्छघाट-सराहन-नारायणगढ़-सैंज
21. शिमला/तारादेवी-कुनिहार-रामशहर-नालागढ़-घनौली
22. नैरी पुल से अनौरा-राजगढ़-बनेठी
23. मंडी-गगल-चैलचौक-जंझैली-छतरी-रामपुर-नागन
24. नारकंडा-बागी-टिक्कर-रोहड़ू
25. तकलेश से नोगली
26. घुमारवीं-जाहु-सरकाघाट
27. हमीरपुर-सुजानपुर-आलमपुर-पालमपुर
28. थाना कलां-बंगाणा-नादौन
29. नादौन-टिहरा सुजानपुर-संधोल-कंडापत्तन
30. बरोटीवाला-पट्टा-अर्की-शालाघाट
31. शिमला-ढली-ततापानी-चुराग-रोहांडा-सुंदरनगर
32. सनौरा-राजगढ़-नौहराधार-हरिपुरधार-रोनहाट-जामली
33. सतौन-रेणुका-ददाहू-जमटा-दो सड़का
34. हरिपुरधार-संगड़ाह-रेणुका
35. कंडाघाट-साधुपुल-चायल-कुफरी
36. हरिपुरधार-कुपवी-तराहन-सराहन-चौपाल
37. सैंज-देहा-चौपाल-नेरवा-फिड़्डुपुल
38. सोलन-दयोठी-सुबाथू-कुनिहार
39. कफोटा-जखाणा-जौंग-दुनियां-हरिपुर
40. रोहडू-चिड़गांव-लरौट-चांशल-डोडरा क्वार
41. नालागढ़-दभोटा-बरूणा-बघेरी-मीरा
42. सनौरा-यशवंतनगर-गौड़ा-डुबलू-जनेड़घाट-छलांडा-जुन्गा-मैहली
43. हाटकोटी-मंद्रोल-ताहु-थरोला-कोटखाई
44. हाटकोटी-तकलेश-न्यूरी
45. बंगा/श्री आनंदपुर साहिब-श्री नैनादेवी-स्वारघाट।

आध्यात्मिक कृषि में छिपा है देश का भविष्य : सुभाष पालेकर

साक्षात्कार

सुभाष पालेकर

भारत में शून्य बजट आध्यात्मिक कृषि तकनीक के शोध, विकास एवं प्रसार आन्दोलन के प्रणेता श्री सुभाष पालेकर पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत के विशेष आग्रह पर हिमाचल प्रदेश चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर में 'शून्य लागत प्राकृतिक खेती' पर आयोजित चार दिवसीय कार्यशाला के संचालन के लिए पधारे। क़ाबिलेग़ौर है कि रासायनिक कृषि से संत्रस्त किसानों, बागवानों और आम लोगों ने अभी जैविक खेती की ओर उ मीद भरी निगाहों से देखना आर भ ही किया था, ऐसे में श्री पालेकर ज़ीरो बजट आध्यात्मिक कृषि की नई धारणा के सफल परीक्षण के साथ देश के सामने आए। किसानों, बागवानों और आम लोगों की पीड़ा को आत्मसात कर इस सुन्दर वसुंधरा को विनाश से बचाने के लिए आध्यात्मिक खेती का सफल दर्शन और तंत्र विकसित कर, उन्होंने कृषि को नई दिशा प्रदान की है। आम लोग या कुल मिलाकर कहें तो अधिकांश कृषक और बागवान अभी भी आध्यात्मिक कृषि या ऋषि खेती के नाम से अनभिज्ञ हैं। किन्तु श्री पालेकर कहते हैं कि हर राजीव को ज़हरमुक्त खाद्य, प्रदूषणमुक्त जल, भूमि, पर्यावरण और सुखी एवं आनन्दी जीवन मिलना ही चाहिए क्योंकि ये तमाम चीजें उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारा यह जन्मसिद्ध अधिकार हमसे अवैज्ञानिक, अमानवीय, ख़तरनाक, विनाशकारी और शोषणकारी हरित क्रान्ति ने छीन लिया है। वह कहते हैं कि हर जीव को उसका यह जन्मसिद्ध अधिकार पुनः दिलवाने के लिए हमने अहिंसक, संवैधानिक, रचनात्मक अराजकीय और नियमी आन्दोलन चलाया है। उन्होंने कार्यशाला में स्थानीय किसानों-बागवानों, कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों, वैज्ञानिकों और छात्रों को बताया कि पूर्व धारणाएं धीरे-धीरे बदल रही हैं और परिवर्तित होनी ही चाहिए क्योंकि आधुनिक कृषि पद्धति ने व्यापक रूप से हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व में खेती को नुक़सान पहुंचाया है; जिसका ग़मियाजा आने वाले समय में हमारी नस्लें भुगतेंगी। वह इन तमाम बातों का हल ज़ीरो बजट वाली प्राकृतिक कृषि में ही स भव बताते हैं। 'समाज-धर्म' के लिए सूचना एवं जन स पर्क विभाग, धर्मशाला के क्षेत्रीय निदेशक श्री अजय पाराशर ने उनसे शून्य बजट पर आधारित आध्यात्मिक कृषि से जुड़े तमाम मुद्दों पर ल बी बातचीत की। पेश हैं पालमपुर में उनसे किए गए साक्षात्कार के महत्वपूर्ण अंशः-

❑ ***लेखक : पालेकर साहिब, आधुनिक कृषि पद्धति या रासायनिक खेती के बाद कॉरपोरेट वर्ल्ड अब जैविक खेती की बात कर रहा है और इसके मध्य आप बात कर रहे हैं ऋषि खेती या प्राकृतिक कृषि की। इन तमाम संदर्भों या धारणाओं के बीच आप अपने आपको किस तरीके से तर्कसंगत पाते हैं? आप किस प्रकार लोगों को आधुनिक कृषि पद्धति और जैविक खेती की बजाय प्राकृतिक खेती की ओर लेकर आयेंगे?***

श्री पालेकर : पिछले कुछ वर्षों में हमारे समक्ष दो बातें प्रमुखता से आई हैं। एक तो परिस्थितियां बदली हैं। नये-नये चैलेंजेज या चुनौतियां खड़ी हुई हैं। जैसे खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है; यह केवल दैशिक नहीं, वैश्विक समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाईमेट चेंज अभी करंट इशु हैं, दोनों ही वैश्विक समस्याएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बिमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, लाखों लोग हर साल मौत के मुंह में जा रहे हैं। भारत में ही नहीं, किसान पूरे विश्व भर में आत्महत्याएं कर रहे हैं। देहातों से शहरों की तरफ सुखाओं का स्थानान्तरण तेज गति से हो रहा है। यह जो सारी परिस्थितियां हमारे समक्ष आ खड़ी हुई हैं, हम पर दबाव डाल रही हैं। हरेक को सोचने के लिए बाध्य कर रही हैं कि जो व्यवस्था हम अब तक डो रहे थे या चला रहे हैं, क्या उसको आगे बढ़ाना ठीक रहेगा? इस व्यवस्था को अगर आगे नहीं बढ़ाना और रोकना है, तो उसके विकल्प क्या होंगे?

रासायनिक खेती ने जितनी भी समस्याएं खड़ी कीं, पूरी दुनिया में इसका हल जैविक खेती के माध्यम से निकाला गया। लेकिन अब मालूम पड़ा कि जिस विश्वव्यापी शोषणकारी महाव्यवस्था ने पूर्व नियोजित रूप में हमारे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में हरित क्रांति को टैक्नोलॉजी विकसित की थी, जैविक कृषि के पीछे भी वही काम कर रही है। हमारा उद्देश्य था-खाद्यान्नों का स्वावल बन, लेकिन जिस महाव्यवस्था ने दोनों कृषि पद्धतियों को हमारे देश में भेजा, उससे उसी का स्वावल बन हुआ। उनके दो प्रमुख एजेंडे थे, पहला था-हमारे देश की अर्थव्यवस्था का दोहन और दूसरा-हमारे प्राकृतिक संसाधनों का नाश करना। रासायनिक कृषि के संसाधन जितने मंहगे हैं, उससे चौगुनी मंहगी है जैविक कृषि। इसका मतलब है कि हमारे किसानों और प्राकृतिक संसाधनों का जितना शोषण रासायनिक कृषि से हो रहा है, उससे चौगुना शोषण जैविक खेती से किया जा रहा है।

लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने हमें स्वदेशी का मंत्र दिया था, पर हम स्वदेशी होने के लिए क्या कर रहे हैं? जिस प्रकार रासायनिक कृषि विदेशी तंत्र है, उसी तरह जैविक खेती भी विदेशी षड्यन्त्र का हिस्सा है। दोनों तंत्रों से प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हो रहा है, किसानों को उत्पादन नहीं मिल रहा, किसान कर्ज में डूब कर आत्महत्या कर रहा है, जहरीले खाद्यानों से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, लाखों लोग मर रहे हैं; फिर भी अगर हम रासायनिक या जैविक कृषि करते हैं, तो यह सीधे-सीधे आत्महत्या करना ही है; चाटे का सौदा है। युवा, अगर, खेती छोड़ कर भाग रहा है, तो भागेगा ही, क्यों रहेगा, वहां जिंदा रहने के लिए है ही क्या?

हर कोई इन समस्याओं का हल तो चाहता है, पर कोई दिशा नहीं मिल रही थी। ऐसे में हमने उस पर काम किया। मैं देख पा रहा था कि मानव विनाश के कगार पर खड़ा है और जो भोगवादी संस्कृति पाश्चात्य राष्ट्रों ने हम पर थोपी है, उसके माध्यम से हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, उससे आने वाली पीढ़ियां बचेंगी कैसे? इसलिए मैंने सोच-समझ कर इस विधि को विकसित किया, अनुसन्धानित किया और आज यह स्थितियां बन गई हैं कि अब हर किसी को समझ आ रहा है कि हम रासायनिक और जैविक खेती का जो विकल्प लेकर आए हैं, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा।

मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, एक राज्यपाल होकर भी सही दिशा में सोच रहे हैं, वो देख पा रहे हैं आने वाले विनाश को। बतौर राज्यपाल वह प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं और अगर वह अपने अधीन विश्वविद्यालयों के माध्यम से इस आन्दोलन को आगे बढ़ाते हैं, तो किसानों को अवश्य नई राह मिलेगी और किसान राहत महसूस करेंगे, वे इसे स्वीकार करेंगे।

❑ ***लेखक : पालेकर साहिब, आप भी पूर्व में कैमिकल फार्मिंग कहें या रासायनिक खेती, के मुरीद थे। आपने न केवल आधुनिक कृषि विज्ञान में स्नातक शिक्षा ग्रहण की बल्कि 15 साल तक उसका अ वास भी किया और उसके बाद आप प्राकृतिक ेती की ओर मुड़े। क्या वजहें रहीं कि कृषि विज्ञान में स्नातक होने के लिए आपने सारी पढ़ाई तो की आधुनिक पद्धति से, फिर अचानक आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया; जिसने आपको अपनी पढ़ाई मध्य में ही छोड़ कर, आधुनिक कृषि से प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित किया और फिर उसे सिर्फ अपने तक ही सीमित न रखने बल्कि उसे समाज तक ले जाने की प्रेरणा दी?***

श्री पालेकर : मैं जब एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ रहा था, प्रकृति में मेरा बहुत ज्यादा विश्वास था। अध्ययन के दौरान मैं आदिवासियों के जीवन पर एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, जिसका विषय था-आदिवासियों की जीवन पद्धति पर स्थानीय पर्यावरणीय व्यवस्था के क्या प्रभाव हैं? पांच दिन मैं कॉलेज में पढ़ता और शनिवार-रविवार को जंगल में जाकर वहां काम करता। मैंने देखा कि जंगल में आम, इमली, जामुन और अन्य सभी प्रजातियों के वृक्षों के साथ, मानो प्रकृति अपने आप साथ खड़ी है। वहां प्राकृतिक व्यवस्था, स्वाबल बी है। मुझे लगा मानो प्रकृति मुझे बता रही है, 'मेरी हुकूमत में किसी मानवीय टैक्नोलॉजी या दखल की आवश्यकता नहीं, मेरी टैक्नोलॉजी स्वीकार करो, वह बहुत अहम है।'

महाविद्यालय में ठीक इसके विपरीत पढ़ाया जा रहा था कि कृषि में प्राकृतिक तकनीक की कोई आवश्यकता नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन सही है और कौन ग़लत? मुझे लगा कि जो मैं पढ़ रहा हूं, वह ठीक नहीं। यूनिवर्सिटी के माध्यम से रासायनिक कृषि पर जो पढ़ाया जा रहा है, ग़लत है, छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। फिर मैं क्यों अपना भविष्य खराब करूं? सोचा कि वापस गाँव लौट जाऊँ। अगर वहीं पढ़ता तो रासायनिक विषय ही पढ़ पाता। मैंने सोचा इसमें ज़रूर कुछ ग़लत है। तब मैं वापस अपने गांव आ गया। मेरे पिता जी स्थानीय पद्धति पर आधारित पार परिक कृषि करते थे। मैंने, जब गाँव जाकर अपने पिताजी से रासायनिक कृषि करने की बात की, तो हड़क प मच गया। सब विरोध करने लगे, ऐसा क्यों कर रहे हो? सब बर्बाद कर दोगे। लेकिन मैंने जो पढ़ा था, उसे जांचना चाहता था कि क्या सही है और क्या ग़लत? मेरे बहुत आग्रह करने पर उनको लगा कि अकेला बेटा है, कुछ कर बैठेगा, तो उन्होंने अनुमति दे दी। इस तरह मैंने रासायनिक कृषि शुरू कर दी, 1973 में। वर्ष 1973 से 1985 तक मेरी उपज बढ़ती रही। लेकिन, जब 1985 से मेरी उपज घटने लगी, तो मुझे धक्का लगा। मैंने सोचा कि महाविद्यालय में जो पढ़ा, अगर उसकी फिलॉसफी सही है, टैक्नोलॉजि सही है, फिर उपज तो नहीं घटनी चाहिए। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, कृषि विज्ञान के टैक्नोलॉजि दर्शन में कुछ तो झाला है, इसे जांचना चाहिए। उस समय पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ० एच०वी० उदयमार्ले, जो मेरे कॉलेज के प्रिंसीपल भी रहे थे, मेरी सामाजिक गतिविधियों के चलते मुझे बहुत प्यार करते थे। मैंने उन्हें बताया कि आपने मुझे जो कुछ पढ़ाया-सिखाया है, वही मैं कर रहा हूँ। अगर आपकी कृषि तकनीक सही है, तो मेरी उपज घटनी नहीं चाहिए थी। ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है या सबके साथ, वह सुनकर वह हंस पड़े। बोले, "सुभाष, मेरे पास तु हारे सवाल का एक ही जवाब है। तुम रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ाओ, नई-नई कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करो।"

मैंने सोचा कि सर के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। मैं वापस आ गया, और ठान लिया कि इस समस्या का हल तो निकालना ही पड़ेगा। उस समय, समाधान, जैविक खेती के रूप में आया था; पर यह भी विदेशी तंत्र है, स्वदेशी नहीं। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, बॉयो ये विधियां हमारे सामने थीं। मैंने शुरूआत में ही इसको जांचना आरंभ कर दिया। तीन साल बाद मालूम पड़ा कि यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसमें उपज तो मिलती नहीं, लेकिन संसाधन चौगुने मंहगे हैं, सरेआम लूट है। जैविक खेती भी किसानों के लिए झूठ है, यह जानकर मैंने इसे छोड़ दिया। अब क्या करें, क्या विकल्प हो सकता है? मेरे जंगल के जो अनुभव और आ यास थे, उन्हें सामने रखकर मैंने मन में कहा कि अगर मुझे कोई सही राह दिखाएगा तो वह प्रकृति ही है। मैं पुनः दो बार जंगल गया और तीन साल तक अध्ययन और शोध किया। इस दौरान जो मुझे प्राप्त हुआ, उस पर 1988 से 2000 के दौरान 12 साल तक अनुसंधान किया। मेरे कुल 154 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिन पर मुकम्मल काम और परीक्षण हुआ है।

-क्रमशः

एक गांव को बनाया विधवाओं का गांव

फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर चाहे लाख विवाद हो और ये कहा जा रहा हो कि ड्रग्स और नशाखोरी को लेकर इस फिल्म के अंदर अतिशयोक्ति की गई है। लेकिन, अगर पंजाब की हकीकत को जानें तो शायद आपको ये धारणा बदल जाएगी। हो सकता है कि फिल्म उड़ता पंजाब को वहां पर आनेवाले विधानसभा चुनाव के चलते नफा-नुकसान को देखते हुए इतना बवाल किया जा रहा हो लेकिन नशे के दलदल में डूबे पंजाब की जमीनी हककीत जानकर आप हैरान रह जाएंगे।

नशे ने इस कदर पंजाब को लील कर दिया है कि वहां के एक गांव 'मकबूलपुरा' को विधवाओं का गांव कहा जाने लगा है। इसकी वजह ये है कि यहां के अधिकतर मर्दों की नशे के कारण मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि पंजाब को जितना नुकसान आतंकवाद के दौर में नहीं पहुंचा, उससे ज्यादा नुकसान नशा कर रहा है।

ड्रग्स की चपेट में 83 फीसद पढ़े-लिखे लोग

इस रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब में नशा करने वाले इन लोगों में से से 99 फीसद पुरुष, 83 फीसद पढ़े-लिखे लोग और 54 फीसद शादीशुदा लोग हैं। 53 फीसद लोग सबसे ज्यादा हेराइन का इस्तेमाल कर रहे है। हालात ये हैं कि रोजाना हेरोइन इस्तेमाल करने वाले इस पर करीब 1400 रुपए खर्च कर डालते हैं। नशा करने वालों में 53 फीसद लोग हेरोइन का सेवन करते हैं जबकि अफीम जैसी चीजों का इस्तेमाल करनेवाले पंजाब में 33 फीसद लोग हैं।

पंजाब में 2.3 लाख लोगों को नशे की लत

पंजाब में ड्रग्स को लेकर वैसे तो कई तरह की रिपोर्ट आती रही है। सभी रिपोर्टों के अंदर इसके गंभीर नतीजे बताए गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेज (एसीआईएम) ने एम्स के साथ मिलकर जो सर्वे पंजाब के 10 जिलों का कराया है उसके नतीजों तो और भी चौंकाते हैं। इस सर्वे के अनुसार, इस समय पंजाब में ड्रग्स और अन्य दवाईयों की जद में करीब 2.3 लाख लोग हैं, जबकि करीब 8.3 लाख लोगों को इस नशे की लत तो नहीं है लेकिन वो भी समय-समय पर इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। यही लोग बाद में चलकर इस नशे में पूरी तरह से डूब जाते हैं।

7500 करोड़ रुपए नशे पर फूंकते हैं पंजाबी

रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब में नशे का कितना बड़ा कारोबार है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहां के लोग 7500 करोड़ रुपए सालभर में नशे करने में फूंक देते हैं। ऐसे नशे करनेवालों में से 54 फीसद लोग शादीशुदा है जबकि 76 फीसद नशा करनेवालों की उम्र सीमा 18 साल से 35 साल के बीच है।

पंजाब की ड्रग्स और अफीम जैसी नशे की खेप आए दिन तस्करों से पुलिस बरामद करती रहती है उसके बावजूद ये कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब के लोगों की जिंदगियां यूं ही ये बर्बाद कर रहा है।

भविष्यवाणी के अलावा बल्ब जला सकता है हमारा दिमाग

इंसानी शरीर में यूं तो हर अंग महत्वपूर्ण होता है लेकिन दिमाग अपने आप में बेहद खास है। आज हम आपको दिमाग से जुड़ी कुछ ऐसे अजब तथ्य बताएंगे जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। दिखने में यह छोटा सा दिमाग बड़े काम का है। शरीर का यह अंग इतना शक्तिशाली है कि एक बल्ब जला दे। जानिए दिमाग के बारे में कुछ रोचक तथ्य-

❖ मस्तिष्क भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं

हमारे दिमाग में एक मिडब्रेन डोपामाइन सिस्टम (एमडीएस) होता है, जो घटने वाली घटनाओं के बारे में मस्तिष्क को संकेत भेजता है। हो सकता है कि हम इसे ही अंतर्ज्ञान अथवा भविष्य के पूर्वानुमान कहते हैं। जिस व्यक्ति के दिमाग में यह सिस्टम जितना ज्यादा विकसित होता है वह उतनी ही सटीक भविष्यवाणी कर सकता है।

❖ मस्तिष्क निद्रा के दौरान अधिक सक्रिय होता है

कहा जाता है एक अच्छी नींद एक इंसान के लिए जरूरी है। लेकिन कोई भी इसके पीछे का मुख्य कारण नहीं जानता है। दिन के दौरान, हमारे दिमाग ऐसी बहुत सी गतिविधियां करता है जिन्हें याद किए जाने की जरूरत होती है, लेकिन एक अच्छी नींद हमारी यादों को स्थिर करने में मदद करती है ।

❖ मस्तिष्क, शरीर की अधिकतम ऊर्जा का उपयोग करता है

मानव मस्तिष्क, शरीर द्वारा उत्पादित ऊर्जा का करीब 20 फीसद उपयोग करता है । मस्तिष्क इस ऊर्जा का प्रयोग याद भावना, केंद्रीय तंत्रिका-तंत्र का प्रबंधन, महसूस करने के लिए प्रयोग करता है ।

किशोरों का दिमाग पूरी तरह से सक्रीय नहीं होता

लोकप्रिय धारणा है की पांच साल की उम्र तक मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित हो जाता है जबकि इसके विपरीत बच्चों के अपनी किशोरावस्था में प्रवेश के दौरान भी उनके दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं। मस्तिष्क के ग्रे मैटर यौवन और विकास के अलावा निर्णय लेने की क्षमता के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। हालांकि, अधिकतर काम के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क के कुछ हिस्से १७ साल की उम्र तक परिपक्व नहीं होते है, लेकिन केवल दूसरों के साथ अनुभव से सीखते हैं और बढ़ते हैं।

❖ दिमाग को नहीं होता दर्द महसूस

हमें कुछ भी चोट लगने अथवा शरीर में कुछ परशानी होने पर दर्द के रूप में मस्तिष्क हमे चेतावनी देता है लेकिन मस्तिष्क का कोई दर्द महसूस कराने का सिस्टम अभी तक नहीं है। मस्तिष्क के चारों ओर की कोशिकाओं के माध्यम से हमे मस्तिष्क के दर्द का अनुभव होता है।

❖ मस्तिष्क में 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं

न्यूरॉन्स बिजली और रासायनिक संकेतों के माध्यम से अन्य तंत्रिका कोशिकाओं या मांसपेशियों को सूचना के भेजते हैं। यदि सभी न्यूरॉन्स एक साथ बिजली उत्पन्न करे तो वह इतनी बिजली राशि उत्पन्न करते है हो एक बल्ब जलाया जा सकता है। यह 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से मस्तिष्क को जानकारी भेज सकते हैं।

❖ सीखने पर दिमाग की झुर्रियां होती है विकसित

मस्तिष्क में गहरी दरारें, और छोटे खांचे होते है जिनकी सतह पर न्यूरॉन्स होते हैं और जब भी हम कुछ सीखते है हमारे मस्तिष्क में एक नई सलवट पड़ जाती है इस वजह से हम ज्यादा सीख पाते है और याद रख पाते हैं।

जल्द मिलेगा सौ रुपये में साल भर का इंटरनेट डाटा

महीने के खर्च में इंटरनेट के खर्च की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रहती है। अब आप मात्र सौ रुपए में साल भर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे सस्ते स्मार्टफोन्स तथा टैबलेट देने वाली कंपनी डाटाविंड अब सबसे सस्ता इंटरनेट भी देने जा रही है। कंपनी वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (वीएनओ) के लिए आवेदन करने जा रही है। इसके बाद लाइसेंस मिलने पर मात्र 100 रुपए में एक साल तक इंटरनेट सेवा देगी।

सरकार वीएनओ के लिए दिशा-निर्देश जारी कर चुकी है। इसके बाद ही डाटाविंड ने मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर परियोजना पर 100 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। डाटाविंड के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीत सिंह तुली ने कहा है कि देश के 100 करोड़ लोग अभी भी इंटरनेट सेवा से वंचित हैं।

तुली ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इंटरनेट के लिए सालाना 1200 रुपए तक खर्च नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से कंपनी मात्र 100 रुपए के वार्षिक शुल्क पर आम लोगों को इंटरनेट मुहैया कराना चाहती है। इस सर्विस के तहत इसके तहत ग्राहक हर तरह से इंटरनेट का उपयोग कर सकेगा। कंपनी अपनी यह सेवा रिलायंस कम्युनिकेशंस और टेलीनॉर के साथ मिलकर मुहैया करा रही है। टेलीकॉम कंपनी वीएनओ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। उनकी कंपनी उसके साथ करार कर दिवाली से पहले ग्राहकों को सस्ती इंटरनेट सेवा देना चाहती है। वहीं दूरसंचार विभाग ने भी इसके लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वीएनओ के लिए आवेदन के 60 दिन के अंदर लाइसेंस मिल जाएगा।

संपादक व प्रकाशक संदीप परमार द्वारा बीपीओ सिद्धबाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा-176057, हि0 से प्रकाशित व संपादित और इम्पीरियल प्रिंटिंग प्रेस, मुरब्बाह रोड धर्मशाला से मुद्रित। फोन नंबर : 01892-235315 Mail : badaltirahain@gmail.com